प्रो॰ राम देव भंडारी(बिहार): सर, हम सत्र के शुरू से ही गुजरात की फर्जी मुठभेड़ के बारे में कह रहे हैं ...(व्यवधान)... सर, सेशन के शुरू से ही गुजरात में हुई फर्जी मुठभेड़ के बारे में बोलना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That has not been admitted. (*Interruptions*) Now, let us take up the Securities Contracts (Regulation) Amendment Bill, 2007. (*Interruptions*) Mr. Trivedi, your matter is over. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record ...(*interruptions*)...Your matter is over. Zero Hour is over. I have taken up some other matter. ...(*Interruptions*)...

SHRI DINESH TRIVEDI:*

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, अनेकों सूचनाएं दी गई हैं ...(व्यवधान)... गुजरात में जो फर्जी मुठभेड़ हुई है ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Notices have either not been renewed or have lapsed. ...(*Interruptions*)... Let us now take up the Securities Contracts (Regulation) Amendment Bill, 2007. ...(*Interruptions*)..

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, यह गलत बिल है ...(व्यवधान)... यह गलत है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: क्या बात है ...(व्यवधान)... आप क्या बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: इनकम टैक्स की चोरी हो रही है ...(व्यवधान)...

The Securities Contracts (Regulation) Amendment Bill, 2007

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration".

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia ...(*Interruptions*)...

---

*Not recorded.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया(झारखण्ड): सर, ...(व्यवधान)... कैसे बोलें, सर ...(व्यवधान)... ऐसे में कैसे बोलें ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amar Singhji, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं ...(व्यवधान)... You are getting up without any notice. You are a senior Member, There is no notice. ...(*Interruptions*)...

SHRI AMAR SINGH(Uttar Pradesh): We have given notice. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is absolutely no notice. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ..(*Interruptions*)...

SHRI AMAR SINGH: We will not allow him to talk. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have not given any notice. What is your problem? ..(*Interruptions*)... The House is adjourned for fifteen minutes.

The House then adjourned at twenty-three minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled at forty minutes past twelve of the clock,

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखण्ड): उपसभापति महोदय, मैं "सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट्स (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2007" के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल को लाने का जो मूल मकसद हे, उस बारे में वर्ष 2005-2006 के अपने बजट-भाषण में हमारे वर्तमान वित्त मंत्री महोदय ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, हाई लेवल की कमेटी ओन कोरपोरेट बांड्स एंड सिक्युरिटाइजेशन और वह उस पर डिसकस करके बताएगी कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा था कि सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, जो 1956 का है, उएसको अमेंड करेंगे। जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने ध्यान में रखी थी, उसके पीछे रीज़न था, जो कॉमन असेट्स हैं सिक्युरिटाइजेशन के, जैसे मोर्टगेज, क्रेडिट काड्र्स, ऑटो लोन्स, कन्ज्युमर लोन्स, स्टुडेंट लोन्स, कोरपोरेट डेट्स रिसीवेबल्स। अब यह तो समझ में आता है कि आज के पहले ऐसे लोन्स की फर्दर कोई सिक्युरिटाइजेशन की व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, यह पहली बार हो रहा है कि जो कर्जा है, अगर किसी बैंक ने कर्जा दिया है, चाहे वह हाऊस लोन के रूप में दिया हो, चाहे वह क्रेडिट काड्र्स के अगेन्स्ट दिया हो, चाहे ऑटो लोन्स के रूप में दिया हो, चाहे स्टुडेंट लोन्स के रूप में दिया हो, चाहे कोरपोरेट एक्ट में दिया हो, उसकी फर्दर सिक्युरिटाइजेशन हो, अर्थात उस लोन को एक रेटिंग एजेन्सी द्वारा टोटली सर्टिफाइड करने के बाद

उसका सिक्युरिटी पेपर स्टॉक मार्केट में भी सेकेंडरी मार्केट में बिक सके। इतना तो समझ में आता है कि हाऊसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन, कंज्युमर लोन, स्टुडेंट लोन इसका तो सिक्युरिटाइजेशन हो, लेकिन यह कोरपोरेट डेट को कैसे लें। आज तक बहुत बार पहले, मेरे ख्याल से जब से देश आजाद हुआ, तब से इस सदम में और खासकर के जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इस सदन में पता नहीं, हजारों बार सदस्यों ने सवाल पूछे होंगे कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों के जो डेट्स हैं, वे राइट-ऑफ कर दिए जाते हैं, उसका ब्यौरा सदन को दिया जाए, परन्तु बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत आज तक वह ब्यौरा सदन को न दिया गया है और न किसी समिति को बताया गया कि किस-किस उद्योगपति का कितना-कितना कर्जा राइट-ऑफ किया गया।

महोदय, सिक्युरिटाइजेशन का जो मेन परपज है, वह यह कि जो एक बैंकरप्सी असेट्स व्हीकल थी, बैंकरप्सी का जो एक प्रावधान था, उसको स्पेशल व्हीकल सिस्टम में लाकर इनको सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट्स रेगुलेशन के तहत लाया जा रहा है। तो क्या मंत्री महोदय ने इन चीजों पर ध्यान देते हुए, वैसे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में यह बहुत दिनों से चलता आया है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमरीका में शुरू हुआ, और कनाडा में शुरू हुआ, किन्तु उन देशों के साथ हमारा स्टॉक मार्किट या हमारे स्टॉक मार्किट की पद्धति या हमारे यहां जो सिक्युरिटी पेपर हैं, उसकी पद्धति मेल नहीं खातीं है। हमारे यहां जो इतना बड़ा IPO Scam हुआ था, उसको अभी तक हम भूल नहीं सके, उससे हम पूरी तरह से अभी तक उभर नहीं सके हैं। IPO की भी जिम्मेदारी SEBI के ऊपर है और इन सिक्युरिटीज़ को सर्टिफाई करने की, जो डिस्क्लोज़र करेंगे कि इन सिक्युरिटीज के बारे में, उसको भी सर्टिफाई करने का अधिकार हमने SEBI को ही दिया है। SEBI क्या उसमें दक्ष हो गया है, समर्थ है, क्या उस व्यवस्था में वाकई उसको सर्टिफाई करने की व्यवस्था है और कल उसके बावजूद भी यदि कम्पनी फेल होती है और सिक्युरिटी पेपर भी फेल होता है, तो क्या गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करेगी? क्योंकि, मेरिका और कनाडा में जो यह पद्धति है, वहां गवर्नमेंट इस सिक्युरिटी पेपर को अथॉराइज करती ै, वह गवर्नमेंट की सिक्युरिटी होती है, तो क्या यहां भी काउंटर गारंटी गवर्नमेंट की होगी और गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, इसकी गारंटी देगी? महोदय, यह बात सही है कि हमारे यहां जब लोन दिए जाते हैं, चाहे वे छोटे लोन हों या बड़े लोन हों, अगर वे डूब जाते हैं तो बैंक भी डूब जाते हैं। छोटे-छोटे बैंक डूब जाते हैं, किन्तु बड़े बैंक नहीं डूबते। हमने देखा था कि नेशनल हाऊसिंग बैंक के चेयरमैन, हर्षद मेहता के टाइम जब स्कैम हुआ, उस समय इतने मजबूर हो गए कि उसके CMD को आत्महत्या करनी पड़ी और ऐसा ही स्कैम कैनरा बैंक में हुआ था और उसके CMD की जब गिरफ्तारी होने वाली थी तो उनको हार्ट अटैक हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कानूनों में संशोधन लाए गए, SEBI का शिकंजा कसा गया, NHB के पूरे कानून को पूरी तरह से 2000 में बदला गया, किन्तु इस सिक्युरटाइजेशन के माध्यम से आप जो पूल बनाएंगे, ऐसे कर्जों के लिए जो पैसा उपलब्ध होगा, क्या उससे होम लोन सस्ते होंगे? क्या आटो लोन सस्ते होंगे? क्या क्रेडिट कार्ड का

रेट आफ इंटरेस्ट नीचे आएगा? मंत्री महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी क्रेडिट कार्ड पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है और क्रेडिट कार्ड पर जो रेट आफ इंटरेस्ट लगता है, वह 36 परसैंट तक जाता है। 36 प्रतिशत तक ! यह कितना महंगा है, इसके बारे में कभी सोचा है? अब आप क्रेडिट कार्ड के लोन को भी सिक्युटराइज करेंगे, वह स्टॉक मार्किट में भी बिकेगा, उसका दिवालिया न हो, उसको इस अमेंडमेंट के माध्यम से एक कवर देंगे, लेकिन क्या क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट सस्ते होंगे? सारी दुनिया में सस्ते हैं। क्या भारत में क्रेडिट कार्ड सस्ता होगा, क्या यह मध्य वित्त परिवार के लोगों को, निम्न वित्त परिवार के लोगो को उपलब्ध होगा, भले ही उसको लिमिट पांच हजार, दस हजार, बीस हजार या पचास हजार है? क्योंकि देखने में तो सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, ब्लैक कार्ड आदि आ गए हैं, लेकिन ये बड़े लोगों के लिए ही उपलब्ध हैं, मध्य वित्त परिवार के लिए और जिनकी कोई फिक्स इन्कम नहीं है, उनके लिए ये उपलब्ध नहीं हैं। उसी तरह से mortgage loan जिसके लिए सिक्युटराइजेशन किया जा रहा है, यह तो जिनकी सेलरी है, जिनके पास सेलरी स्लिप है, उनके लिए उपलब्ध होगा, लेकिन क्या यह साधारण लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा? जो नौकरी नहीं करता है, उसके लिए भी यह उपलब्ध होगा? हमारी टोटल जनता में कितने लोग हैं, जो केवल नौकरी से अपना गुजारा चलाते हैं? ऐसे लोग बहुत कम हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ इम्प्लायड हैं, क्या उनको ये कर्जे उपलब्ध होंगे? महोदय, सिक्युटाराइजेशन का यह पहलू लेने से पहले, जो आपने हाई लैवल एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी, उसके पहले क्या कुछ अलार्मिंग सिचुएशन आपके सामने आई थी? क्या आपको लग रहा था कि हाऊसिंग लोन का एक रेड अलर्ट आ गया है, क्रेडिट कार्ड का या स्टूडेंट कार्ड का एक रेड अलर्ट आ गया है? आज भी छात्रों के लिए स्टूडेंट लोन का नाम तो लिया जा रहा है, किन्तु छात्रों को स्टूडेंट लोन मिलता नहीं है। बार-बार मंत्री महोदय ने इस सदन में घोषणा की कि सात लाख रुपए के लोन तक कोई collateral security नहीं लगेगी, किन्तु उसके बावजूद अगर एक छात्र बैंक में स्टुडेंट लोन लेने के लिए जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि कोलैट्रल सेक्योरिटी क्या दोगे? अगर कोलैट्रल सेक्योरिटी नहीं दोगे तो बैंक से लोन उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीजों की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा सोचा जाना चाहिए।

महोदय, इस तरह से एक पहलू तो यह है कि जिनको आप कवर रहे हैं, क्या वह साधारण जनता के लिए उपलब्ध होगा? दूसरा जब ये सेक्योरिटी पेपर सेबी एप्रूव कर देती है, तो वह स्टॉक मार्केट में बिकता है। पहले स्टॉक मार्केट में केवल गवर्नमेंट के बैंकों की ही इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी, लेकिन अब साधारण ब्रोकर या साधारण बायर भी इसमें डील कर सकता है। महोदय मेरे सलाल बहुत साधारण से हैं।

जब से स्टॉक मार्केट चढ़ने लगी है, तब से हमने देखा है कि हर टीवी चैनल का अलग से एक बिजनेस चैनल आ गया है। हिन्दी, इंगलिश, बंगाली, तमिल, हर लैंग्वेज में यह चैनल आ गया है और मैं देखता हूं कि इन चैनल्स में कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, लोग टेलीफोन के माध्यम से इन

एक्सपर्ट्स को फोन करते हैं और पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक लिया जाए? अब उस स्टाक के माध्यम से ये सेक्योरिटी स्टॉक भी बिका करेंगे। फिर आएगा कि साहब, इसका ले लो, यह ठीक है, किन्तु जरूरी है कि उसका डिस्क्लोज़र प्रॉपर हो, स्क्रीन पर उसका डिस्प्ले प्रॉपर हो और जो सवाल करने वाला आदमी है, उसे पूरी बात समझ आ सके, जैसा कि in the case of IPO. बार-बार सवाल पर सवाल होते हैं और उसका due diligence करने के बाद भी IPO Scam हो गया, क्योंकि IPO Scam Demat के साथ interconnected है। स्टॉक मार्केट में और भी जो बहुत सारे घपले हो गए, उसके कारण Demat fictitious name से PAN Account, Fictitious name से और सारे ऐसे account चलाए जा रहे हैं, जिनके कारण से वहां पर downfall हुआ। क्या उन सारी चीजों की प्रोटेक्शन हम इस सेक्योरिटी पेपर को दे सकेंगे? क्या इसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई कमेटी बैठा कर, उनसे पूछा है? क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि जिस समय यह पेपर केबिनेट के लिए फॉर्मुलेट हो रहा था, उस समय सेबी के ऑफिसर्स आए थे, उन ऑफिसरों ने जो सलाह दी थी, उसे नहीं माना गया। कमेटी के सामने उपस्थित हो कर सेबी के ऑफिसर्स ने कई चीजें बताईं थीं कि अगर कमेटी इसको माने तो इसमें ये-ये चीज़ें नहीं ली गई हैं, लेकिन कमेटी ने उसे मानना क्या था, बिल को वैसे का वैसा ही यहां पर भेज दिया है और उसी बिल को हम पास करने जा रहे हैं।

महोदय, मेरा सवाल यह है कि जो सेक्योरिटी पेपर इंडिया द्वारा इश्यू होंगे, क्या फॉरेन पार्टीज उससे इन्वेस्ट कर सकेंगी? Can foreign parties invest in security papers issued in India? Can cross-border transaction be expected in future in this? क्योंकि यह बड़ी alarming situation है। मेरे पास पुराने फिगर्स उपलब्ध हैं, अगर वे कम हों तो मंत्री महोदय उसमें संशोधन कर दें। हमारे यहां पर आज की तारीख में सेबी द्वारा एप्रूव्ड 1033 FII हैं। ये FII हमारा सेक्योरिटी पेपर खरीदते हैं, क्योंकि विदेशों में उनको पैसा सस्ता मिलता है और फिर वे उसकी इन्वेस्टमेंट और अधिक पैसा बनाने के लिए यहां पर करते हैं। एक तरफ आप individual बैंकों को एलाऊ नहीं करते कि वह लंडन, लक्ज़मबर्ग या किसी दूसरी जगह से सस्ती दर पर पैसा ला कर, लोन ले कर, यहां पर डॉक्युमेंट जमा करके या फिक्स डिपॉज़िट करके, उसमें से इंटरेस्ट कमाए। क्योंकि अगर उसे वहां पर 3% पर पैसा मिलता है तो यहां इन्वेस्ट करके ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आप उसे एलाऊ नहीं करते। आपके बैंकों में यह गाइडलाइन दी गई है कि massive amount का कोई भी long term deposit नहीं लिया जाएगा। तो ये जो FII हैं, जिनके पास में सस्ता पैसा उपलब्ध है, जिस पर rate of interest कम है, वह जब इस सिक्योरिटी पेपर पर इंवेस्ट करता है तो वह ज्यादा पैसा बनाता हैं तो उससे हमारी जो आम जनता है यहां की, हमारे जो बैंक हैं, जिनका पैसा कॉस्टली है, जिसका कॉस्ट ऑफ मनी इज हाई।

What will they do? How will they compete? Ultimately, the entire security market will go into the hands of FIIs. Tomorrow, if they withdraw, what will

happen? Who will take the guarantee? You have brought this Bill to save the banks and lenders from insolvency. That is why you are creating this market. You are allowing the banks not to put this money in their balance-sheet.

आपने जो तीन-चार मुख्य कारण लिखे हैं:

"Besides other advantages, securitisation (a) allows banks and financial institutions to keep these loans off their balance-sheet, thus reducing the need for additional capital." On the one hand, you are saying that they should increase company's authorised capital and here you are saying that the financial institutions and the banks can remove the lending from their balance-sheet.

फिर आपका जो सी॰आर॰आर॰ है जो मेंडेटरी सब्जेक्ट है आर॰बी॰आई॰ के बैंक को, वह भी लागू नहीं होते, वह भी अलग हो गए। एस॰एल॰आर॰ और सी॰आर॰आर॰ के जो नार्म्स हैं उससे भी वे वंचित हो गए। तो क्या इस पर ध्यान दिया गया। फिर दूसरा कहा कि:

"Provides the banks and financial institutions with alternative forms of funding risk transfer, a new investor base, potential capital relief and capital market development."

महोदय, आपने फंडिंग रिस्क फैक्टर को जो आपके यहां पर नॉन परफार्मिंग एसेट्स का या बैड डेट की संख्या बढ़ गई थी आप इन फ्यूचर इसके माध्यम से यह बर्डन जनता के ऊपर डाल देंगे जो सिक्योरिटी पेपर पर इंवेस्ट करेगा, उस पर डालेंगे। और सारी चीजें तो मैं मानता हूं किन्तु कारपोरेट डेट को आप इस में क्यों लाए? Why have you brought corporate debt under this? They are coming here, making money and developing their financial position through the market, through IPOs by selling their shares. If IDBI, IFCI, UTI or any other banks have financed a company or they have invested money in that, it is further securitised. The next step will be insurance. I would like to know whether these things will be insured or not.

फिर आपने कहा है कि "Can reduce lending concentration, improve liquidity and improve access to alternate sources of funding for banks and financial institutions." घूम फिरकर वह बात आती है। महोदय, मैं कभी-कभी सोचता हूं कि हमारा जो आर॰बी॰आई॰ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी मानते हैं, आर॰बी॰आई॰ एक रेग्यूलेटर भी हैं बैंकों का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है। और जो गाइड-लाइंस इनके द्वारा इश्यू भी होती है यह गाइड-लाइंस भी गाइडेड होती है टोटली पॉलिसी ऑफ

1.00 P.M.

दि गवर्नमैंट। जो ऑटोनॉमी है आरबीआई की वह कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। इन्होंने फर्स्ट फरवरी, 2006 को अपनी गाइड-लाइंस ऑन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टेंडर्ड एसेट्स, उसके डेफिनेशन देकर बाकायदा एक गाइड-लाइंस इश्यू की। इंग्लैंड में यह बात बहुत दिन की गई, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और अल्टीमेटली जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था जो उसका सैंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड था, जो उसका रेग्यूलेटर भी था उन्होंने उसको बदलकर अलग से रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी खोल दी। हमारे भारत में जब आप बैंकिंग सैक्टर में और फाइनैंशियल सैक्टर में इतनी न्यू पालिसीज़ और न्यू एक्ट ला रहे हैं और इतना लिबरलाइजेशन ला रहे हैं और इतनी ट्रांसपरेंसी लाने के लिए आप सारी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे सेबी को आपने आज तक इंडिपेंडेंट रखा है, उसी तरह जो आरबीआई रेग्युलेटर है, उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या उसको सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टेटस से टोटली अलग करेंगे? क्योंकि वही गाइडलाइन्स यहां इश्यु कर रहा है, "Allow banks and financial institutions to keep these loans off their balance sheet." फिर कहते हैं, "Reduce lending concentration, improve liquidity and improve access to alternate sources of funding for banks and financial institutions."

महोदय, फिर जो दूसरी तरफ आरबीआई के नार्म्स बनते हैं, वे उनको बाईपास करने का रास्ता भी देते हैं। इस पर क्या मंत्री महोदय ने ध्यान दिया है? आप आगे कहते हैं, "Facilitates better matching of assets and liabilities and development of long-term debt market."

महोदय, आज की डेट में हमारे यहां हाउसिंग लोन महंगे होने का मूल कारण यह है कि शायद 15 साल, 20 साल से ज्यादा का लोन नहीं मिलता है। सारी दुनिया में mortgage जो है, वह 25 साल, 30 साल 35 साल की होती है, लेकिन इसका हमारे यहां सिस्टम नहीं है। हमारे यहां आज तक जो सेक्योरिटी पेपर है, वह ट्रस्ट एक्ट के माध्यम से चलता था, उसको अमेंड करके आप SARFAESI Act लाये और उसके माध्यम से आप इसको डील करना चाहते हैं। यह एक अच्छी पहल है, but with a big question mark. क्योंकि जो हमारा पर्सनल एक्सपियरैंस है, जो हमने पीछे दो स्टॉक स्कैम देखे हैं, पहला तो सेक्योरिटी स्कैम ही हुआ था, सेक्योरिटी पेपर का ही स्कैम था और दूसरा स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ। तीसरे जो सेक्योरिटीज़ पेपर बैंकों से हटकर आम जनता के लिए खरीद-बिक्री के लिए सैंकेडरी मार्केट में उपलब्ध होंगे, इसको स्कैम से बचाने के लिए आपने क्या प्रॉविजन्स रखे हैं? मैं इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपना भाषण समाप्त करते हुए धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अमर सिंह: धन्यवाद उपसभापति जी। मैं सदन का समय विस्तार से अपनी बात कह कर नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं भाई अहलुवालिया जी के वक्तव्य से काफी हद तक सहमत हूं। माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। यहां पर कई तरह के विधेयक सदन के पटल पर प्रस्तुत

किये जाते हैं और हर विधेयक का तात्पर्य लोकसेवा, जनहित से संदर्भित होता है। जैसा कि अहलुवालिया जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि छात्रों को बिना को-लेटरल सेक्योरिटी के पैसे नहीं मिलते हैं, आम आदमी के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, उसी तर्ज पर मैं कहना चाहता हूं कि हम कोई भी कानून बनायें, हम कोई भी तथ्य बनायें, उसका सलेक्टिव यूज़ नहीं होना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले दिनों सीएजी की रिपोर्ट आयी और सीएजी की रिपोर्ट में खिलाड़ियों के साथ-साथ बड़े-बड़े corporate giants के बारे में भी जिक्र किया गया। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर के साथ-साथ रिलायंस और टाटा को भी कई सौ करोड़ रुपये की छूट दे दी गयी। इन्कम टैक्स अधिकारियों का सचिन तेंदुलकर और गावस्कर के लिए तो यह वक्तव्य आ गया कि उनको गलत छूट दी गयी, लेकिन रिलायंस और टाटा के बारे में इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल मौन रहा। इसी सदन में, पहले मैंने कई सौ करोड़ रुपये की अनियमितता का मामला वेदांत विलियर्ड का उठाया था। बार-बार वित्त मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसकी वसूली की जाएगी और अब मामला अदालत के विचाराधीन है इसलिए इसमें कुछ नहीं हो रहा है। आज यह जो क्रोनी केपिटलिज्म चल रहा है खिलाड़ियों को आप भले छूट दे दें, तेन्दुलकर को छूट दे दें, गावस्कर को दे दें, वह तो क्षम्य है क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, लेकिन कई सौ करोड़ की छूट टाटा को दे दी गयी, कई सौ करोड़ की छूट रिलायंस को दे दी गयी और आयकर अधिकारी एक शब्द नहीं कह रहे हैं। सचिन तेन्दुलकर के लिए तो कह रहे हैं कि छूट गलत हो गयी लेकिन टाटा और रिलायंस को खुला मैदान दे दिया गया है, वेदांत विलियम्स को खुला मैदान दे दिया गया है, अनिल अग्रवाल और स्टरलाइट को खुला मैदान दे दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से कानून और प्रावधान बनता रहा कि जो आपके चहेते हैं, जो सरकार के चहेते हैं, उनके लिए एक कानून और जो सरकार के चहेते नहीं हैं, उनके लिए दूसरा कानून-कब तक यह चलता रहेगा? कब तक इनकम टैक्स को आप अपने विरोधियों का दमन करने का औजार बनाते रहेंगे? कब तक रेड राज चलाते रहेंगे? यह कई सौ करोड़ रुपए का घपला है और यह रिपोर्ट अमर सिंह की, समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट माननीय वित्त मंत्री जी, Comptroller and Auditor General ने इस सदन में पेश की है। आपके आयकर अधिकारी सचिन तेन्दुलकर के लिए कहते हैं कि वह दोषी है, लेकिन रिलायंस के लिए और टाटा के लिए एक शब्द नहीं कहेंगे। नेता वह होता है जिसका नेत्र, नीति और नीयत तीनों ठीक हों। आपके नेत्र में भी गड़बड़ है, नीति में भी गड़बड़ है और नीयत में भी गड़बड़ है। कृपया इसे सुधारिए, अन्यथा कोई प्रावधान और बिल मत लाइए। सदन के सदस्य, हम जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे और आपके हर अन्याय और इस तरह के क्रोनी केपिटलिज्म का डटकर विरोध करेंगे।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): धन्यवाद उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा बिल सदन में पेश किया है जिसके जरिए अब, जो

वित्तीय संस्थाएं, जो बैंक, जिनका बहुत पैसा कर्ज में डूब जाता था, जिनका बहुत सा धन डूब जाता था, वे कम से कम इसको रिकवर करने की स्थिति में होंगे। जो स्क्रूटनाइज़ेशन का उन्होंने इसमें प्रावधान किया है, निश्चित रूप से अगर एक बार उनको ट्रेडिंग की फेसेलिटी मिली तो इसका न केवल वेल्यूएशन बढ़ेगा बल्कि उसके अलावा उन एसेट्स की कई गुणा कीमत बढ़ेगी जिसका लाभ न केवल वित्तीय संस्थाओं को मिलेगा, बल्कि उस व्यक्ति को भी मिलेगा जो इसकी वजह से सफर कर रहा है। मान्यवर, स्टेंडिंग कमेटी के सामने यह बिल गया था। स्टेंडिंग कमेटी ने, जो इसमें सुझाव आए थे, कुछ संशोधन किए थे। उन संशोधनों को पास करने के बाद इस बिल को सामने लाया गया है और मुझे लगता है कि इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। जो इनसॉलवेंसी की प्रॉब्लम बार-बार जेनरेट हो जाती थी, उसकी वजह से तमाम तरह की वित्तीय संस्थाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बैंकों को सामना करना पड़ता था, उसका हल भी इससे निकल सकता है क्योंकि अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि इस एक क्षेत्र को इससे क्यों रोका गया था? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं-नेशनल हाउसिंग बैंक का। नेशनल हाउसिंग बैंक को काफी कुछ नुकसान हुआ क्योंकि वह सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता था। अगर इस बिल के माध्यम से एक ऐसा रास्ता मिलता है जिससे नेशनल हाउसिंग बैंक को यह अनुमति मिल जाती है कि वह ट्रेडिंग के रास्ते पर जा सके तो निश्चित रूप से न केवल उसका नुकसान बच जाएगा बल्कि एक सुदृढ़ संस्था के रूप वह सामने आएगा। मान्यवर, एनपीए की बात पहले भी आयी थी। तीन साल पहले तक एक लाख करोड़ से ऊपर तक एनपीए चला गया था। पिछले तीन साल में, मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि तमाम इस तरह के काम हुए, जिनकी वजह से 68 हजार करोड़ की रिकवरी बैंकों ने की है और जो एनपीए है, उसमें काफी कमी आयी है। सरफेसी लॉ की वजह से जो लेंडर हैं, उनको भी वित्तीय संकट से डूबने से बचाया जा सकेगा। मैं एक सुझाव भी मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जो डिफॉल्टर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे डिफॉल्टर गड़बड़ हैं। कई बहुत जेनुइन डिफॉल्टर भी होते हैं जिनको काम धंधा करने में घाटा हो जाता है जिसकी वजह से उनका पैसा डूब जाता है। उनकी वित्तीय संस्थाएं या बैंक उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लेते हैं और इसके बाद ये बाज़ार में उस सम्पत्ति को बेच देते हैं, वह बहुत कम दामों पर बेच दी जाती है। अगर उस सम्पत्ति का प्रॉपर वेल्युएशन होकर उनको ट्रेडिंग की अनुमति हो तो उनकी सम्पत्ति का, एसेट्स का वेल्युएशन भी बढ़ जाएगा। उसकी वजह से दस करोड़ में जिसकी सम्पत्ति जा रही हो और पचास करोड़ उसकी सचमुच कीमत है, तो उस डीफॉल्टर को भी उसका उचित मूल्य मिल जाएगा और उसकी वजह से जिंदगी भर के लिए यह टीस उसके मन में नहीं रहेगी कि हमारी जो सम्पत्ति थी, वह कौड़ियों के भाव में बिक गई। इस बिल से उसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, इसके अलावा, Sir, securitisation converts illiquid loans or assets that cannot be easily sold to third party investor into liquid, makretable securities, Secondly, securitisation allows banks and financial institutions to keep these loans

off their balance sheet, reducing the need for additional capital. This is very important, Sir. They can generate additional capital because it will be off the balance sheet. Thirdly, Sir, it also provides banks or financial institutions with alternative forms of funding risk transfer, new investor base, potential capital relief and capital market development. Apart from that, securitisation can also reduce lending concentration, improve liquidity and improve access to alternate sources of funding for banks and financial institutions. So far alternative sources for funding of financial institutions was a major problem. With the passage of this Bill, that problem will also be resolved. It can also be used to obtain regulatory capital relief or for more efficient capital allocation which is very important and vital thing, as far as the trading and financial management is concerned. Securitisation facilitates attainment of funding at lower cost as a result of isolating the assets from potential bankruptcy risk of the originator. Lower funding costs are also a result of movement of investments from less efficient debt markets to more efficient capital markets through the process of securitisation. It facilitates better matching of assets and liabilities. It also facilitates for development of the long-term debt market. For the investor, it provides diversified pools of uniform assets.

Sir, I think, keeping all these aspects in mind, this is a welcome Bill. Sir, Mr. Ahluwalia has raised certain apprehensions. I think, he should not be concerned about those apprehensions because the hon. Minister is already taking care of those apprehensions. The hon. Member should rest assured that nothing would be done which hampers the interests of the common man, the financial institutions, and the Government banks. The Bill is really going to help the financial health of these institutions and the recovery of the NPAs. It will also help the lenders. So, I would like to request the House to support the Bill. With these words, I conclude my speech and once again, I support the Bill.

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, I rise to support the Bill. Acutally, Sir, it was an old Act by the name of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956. This is an amended form of the earlier Act of 1956. This Bill was introduced in the House in 2005 and referred to the Standing Committee. The Government accepted all the recommendations of the Standing Committee. This Bill has now again come to the House incorporating the recommendations of the Standing Committee. The

question is, what was the need to amend the earlier Bill of 1956? It would say that the basis of the amendment is, the potential of the market, international trends, consultations with major institutional participants and market experts. So, these are the things which have necessitated the amendment of the earlier Act which was passed by the Parliament in 1956. So, in this perspective I would like to support this Bill. This Bill will allow the banks and financial institutions to keep these securitised loans off their balance sheet,—it has already been mentioned by my other colleagues—thus reducing the need for additional capital along with giving them an alternative form of funding risk transfer, a new investor base and potential capital relief.

Sir, everybody knows that securitisation is a form of financing, involving pooling of financial assets and the issuance of securities that are re-paid from the cash flows generated by the assets. This is generally accomplished by actual sale of the assets to a bankruptcy-remote vehicle, that is, a special purpose vehicle, which finances the purchase through the issuance of bonds. These bonds are backed by future cash flow of the asset pool. The assets for securitisation transactions include mortgages, credit cards, auto and consumer loans, student loans, corporate debt, export receivable and off-shore remittances. These are the main things dealt with by the said Bill. Suppose it is very much required for the present economic scenario of the country. Acutally, Sir, in order to get protection from insolvency, it is very much required. I will not take much of your time but there are one or two points, which I would like to submit. Mr. Ahluwalia has already mentioned those things, that is, credit card and student loan. I suppose that so far as credit card system is concerned, there is no monitoring system in the country. Those who are giving credit card to us give us the authority to get loan against that credit card. It can be taken by any citizen. But what is the rate of interest? Sometimes this rate is more than two-and-a-half per cent per month and sometimes it is two per cent. Acutally it is going up to 34 to 36 per cent per year. There is no monitoring system. So, I would like to suggest to the hon. Finance Minister who is here to do something in this regard. Actually, credit card is not a luxury today. It is very much needed by middleclass. It is very much required by them as we require it. It is a very essential instrument provided to a section of the people of the country. The second thing is about student loans. We are popularising the student loans among the common masses. The

students belonging to wretched families, they cannot even reach the threshold of banks to get student loans in a soft manner. So, I would request that in this perspective the matter may be looked into and with these words, I would like to conclude my speech. Thank you.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. This Bill was initially introduced in the Lok Sabha and then it was referred to the Standing Committee on Finance for examination and report. The Committee presented its report in Lok Sabha recently. The Committee recommended a modified approach for regulation and development. The Government after having examined the recommendations of the Committee on Finance withdrew the original Bill, which was introduced earlier and moved a revised version, which is the Securities Contract Regulation Amendment Bill. Sir, securitisation is a form of financing that can be repaid from the cash flow generated by assets. Sir, normally banks give mortgage of housing loan, automobile loans, credit card outstanding loans, and students loans to different individuals. Banks need to have adequate money in order to finance further loans to facilitate this. This Bill provides a mechanism. This mechanism enables banks to pool various types of loans and issue bonds which are called Securitisation Certificates. They have been permitted in India through the National Housing Bank Act and Securitisation and re-construction of financial assets and enforcement of Security Interest Acts. But the security contracts regulations does not recognise it so far. So, therefore, they cannot be traded on the stock markets. This amendment Bill includes these types of Securitisation Certificates in the definition of securities. So, after the Bill is passed the security certificates can also be traded in the stock markets. This is the provision in the Bill. So, there is nothing controversial in this. I support this Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am deeply grateful to the hon. Members. This might appear to be a highly technical issue, but it is not. As the last speaker mentioned, while the language is very technical the underlying concepts is quite simple. Where a loan is granted to a borrower, as far as the lender is concerned, it is an asset in his hand. If a loan is a seven-year loan, the asset has to remain a performing asset for seven years. If it is a twelve-year loan, the asset has to remain a performing asset for twelve years. There are risks. Secondly, if the lender gives a hundred crores for a period of seven years then that 100 crores is blocked for seven years. The

asset that he has, namely, a document under which the borrower agrees to repay him which secures the loan is an illiquid asset. So, world over, what has happened is, new instruments have been developed to make illiquid assets liquid and to reduce the risk of long-term lending. Once illiquid assets are made liquid then the lender has more money to lend. The way that has been found to deal with the issue of making illiquid assets liquid and to reduce the risk for the lender is to invent an instrument called a security and, then, securitise it and sell it to others. What really happens is, instead of the risk remaining entirely on the lender, the risk is now distributed to any number of people who buy the securities. I think, all hon. Members who have spoken on this issue have understood the basic concept. I do not have to explain it in great detail. This is an instrument available widely throughout the world and we are trying to introduce it. In fact, we made a beginning with amending the National Housing Board Act. The Housing Board aggregates its mortgages and issues securities against the mortgages and spreads the risk to others and makes what was originally an illiquid asset into a liquid asset. That market has not taken off. NHB has had some success but in the absence of active trading, an active debt market, an active trading in securities in a debt market. NHB has only been able to register partial success. We also provided for it in the SARFAESI Act. In fact, the SARFAESI Act recognizes securitization. In fact, "S" in SARFAESI stands for 'Securitization'. So, this is not a new concept. It is a concept that is prevalent throughout the world. We made a beginning with the NHB Act and the SARFAESI Act. And, now, we want to take it forward. That is why we are bringing this Bill.

I must also say that this is a good example of how a Standing Committee of Parliament can add great value to a Bill. This Bill is a good example of how a Standing Committee, after taking evidence from the SEBI and others can help the Government to improve the Bill. That is why we have withdrawn the old Bill and introduced this new Bill, rather than making too many complicated amendments. We have accepted the Report of the Standing Committee in toto. The first three recommendations of the Standing Committee have been accepted and the amendments are being made to that effect. One of the recommendation was that the instrument shall be issued according to regulation. The Standing Committee said that this should be based on disclosure-based instrument. We have accepted that, like any other security. When it was done through a public offer, the

document has to be approved by the SEBI. The second recommendation was, as I said a little while earlier, it should be a disclosure-based regulation. We have accepted it. And, the third recommendation to enable the SEBI to regulate the issue and trading of securitized instruments by regulations. And, we will make consequential changes to two other provisions. That has also been accepted. Therefore, we have changed the structure of the Bill and we are accepting the recommendations.

What will happen is, we will create an active securities market. These securities will be traded. Banks will buy these securities. Of course, other financial institutions will buy these securities. The FIIs will also buy these securities. Retail investors was also buy these securities. As people gain experience in dealing with securities, I expect a very large market in securities to be developed. Sir, since these securities can be listed abroad also and when the securities are listed abroad, investors abroad will also buy these securities and, to that extent, the risk that is confined to India would spread to other countries and our risk is minimized and other investors, who have faith in the Indian market, will share the risk and that is good for the country. All kinds of loans, all kinds of assets, all kinds of receivables can, indeed, be securitized. Regulations will be framed by the SEBI about eligibility, about conditions, about investment, etc. All these will come under regulations. Now, how this market will develop, which loans will be securitized first, which receivables will be securitized first, I cannot say. It depends upon how inventive, how innovative origination of a security is and what appetite it can generate in the market. I would assume that mortgage-backed securities will have a ready market, because there is physical asset behind that. I would assume that loans given against immovable property will have good securities market. Some other securities may take sometime to develop. So, these are the things which we will have to leave to the market. I am confident that once securities are recognized to include all kinds of loans, all kinds of receivables, we create an active securities market. We allow for these securities to be traded, allow for the risk to be spread, allow for illiquid assets to be converted into liquid assets then the market will develop. Take for example, the asset management companies. When the first. Asset Reconstruction Companies were floated, the market was a very nascent. It took sometime to develop. But, today, it is a very active market. there are ARCIL and other asset reconstruction companies which are willing to buy bad debts, reconstruct it and sell it, so

that illiquid assets become liquid. This is the way more capital is developed for the market. This is the way more capital is provided for economic activity. And, Mr. Hassan, rightly pointed out that when the structure of economy is changing, it requires all kinds of financing and innovative instruments. These instruments are required. And that is why, broadly, everybody has welcomed these instruments.

Sir, as far as specific questions are concerned, my friend Ahluwaliaji, continues to live under the shadow of the original IPO scam. Nobody disputes that the original IPO scam was a very bad development for the Indian market. But the market has developed a great deal. More regulations are in place. There is a more vigilant regulator which has gained experience. I doubt that a scam of that kind can occur now. I don't we think we need to worry too much about the scam that occurred 15 years ago. A scam of that kind cannot occur now. Far more vigilant, far greater, far stronger regulations are there today. So, I don't think that will happen again.

Hon. Member, Rajeev Shuklaji, asked about the net NPAs. My colleague had disclosed this to Parliament the other day. The net NPAs of the public sector banks, as on 31.3.2007, were the lowest ever, that is, 1.18 per cent. Our goal is to push it to below one per cent. I am confident, by the end of this financial year, we will take it to below one per cent.

SHRI S.S. AHLUWALIA : What is the amount?

SHRI P. CHIDAMBARAM : See, the amount will look large. But the total outstandings are larger. That's why the proportion is 1.18. There is no country in the world with a net NPA of zero...*(Interruptions)*... No; no. both. Absolute amount of the NPAs has come down. And, as a proportion of net outstanding also, it has come down. Figures are available, but not readily. I remember this figure of 1.18 because ...*(Interruptions)*... Last year, in 2006-07, the recovery has been 68,000 crore. I remember this figure of 1.18 because I have used it on many occasions. Last year, I was using the figure of 1.30. This year I am using the number of 1.18. It is the lowest ever NPA. Our public sector banks are much stronger today. That's why they are able to lend much more. They are financing a much larger part of the GDP.

Sir, there was some complaint about the credit cards and students' loan. I think a couple of months ago, the RBI had issued revised guidelines

for credit cards issuing companies. I will send a copy of the guideline to Mr. Hassan. It will take some time for these companies to comply with these guidelines because once new guidelines come, it takes some time. There will be some aberrations. There will be some violations. I am not disputing that. That's the way people function. But we will take action if they persistently violate these guidelines. The RBI has issued some guidelines and I will send a copy of that to you. So far as students' loan is concerned. five years ago, nobody spoke about students' loan. Today, we are talking about students' loan. That itself is progress. That itself shows that students' loans are being given ...*(Interruptions)*... Just a moment, I will answer. I know your question ..*(Interruptions)*... That itself shows that there is a greater consciousness that people are entitled to students' loan. The last number I have is, nine lakh students have been issued students' loan. The outstanding amount is Rs. 12,000 crores. When this Government came into office, it was about Rs. 4,000 crores. It has trebled in three years. But that does not mean that every student has got a loan. It means that every student who gets a loan ...*(Interruptions)*... Wait! Wait! Wait! Out of ten students, there is perhaps a student who deserves a loan but has not got it. But four years ago, five years ago, ten years ago, nine of the ten students did not get loans. May be, today, two out of ten students do not got loans. But, at least, eight out of ten are getting loans. These numbers don't lie. The number of students' loan has multiplied multi-fold. The amount of students' loan has also increased manifold. But I have said publicly and I have repeatedly said if there is any student anywhere in India, who satisfies the criteria, does not get a loan, all I want him or her to do is to send me a postcard saying, "I went to this bank. I asked for a loan and I have not got a students' loan." I have system in my office which tracks down every single complaint on students' loan. Please don't send me complaint of every loan. I am only talking about students' loan. I am only talking about students' loan. I have taken personal responsibility of the students' loan. We are personally monitoring student's loan because I believe that every boy or every girl is like our own son or daughter. If our son or daughter is qualified to get admission into a college and he or she cannot pursue his or her study because he or she does not have money, how bad will we feel? That's how every parent will feel. I have taken it as a personal responsibility. Just please send me a postcard mentioning name of the student and the name of the bank. That's all I want and I will take action.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (Madhya Pradesh): Sir, one minute...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has given an assurance...*(Interruptions)*...

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: I appreciate the Minister. What he has said is correct that lot of students are getting loans. But, at-the same time, if students of professional courses like MBBS or students going abroad want loan of Rs. 7, 8 or 10 lakhs, or something like that, then banks insist on giving guarantee or collateral.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes, that is true...*(Interruptions)*...

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: And, those who cannot give it, are not able to get the loan...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He will clarify that...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, up to Rs. 4 lakhs, there is no collateral, Ninety per cent of the loans are up to Rs. 4 lakhs. There is no collateral for that. Only the father or the mother, along with the student, have to sign. There is no collateral. Above Rs. 7 lakhs or something like that, I do not remember the figure off hand...*(Interruptions)*... Up to Rs. 7 lakhs there is no collateral. There is a collateral above Rs. 7 lakhs. There is a collateral for foreign studies, which is upto Rs. 15 lakhs. But, I cannot now say that a Rs. 15 lakh loan should be without a collateral. It is very difficult for me to tell this to banks. What will happen is...*(Interruptions)*...

SHRI C. PERUMAL (Tamil Nadu): Sir, only one second. ..*(Interruptions)*.. I raised this matter on an earlier occasion also in this august House. The Minister wrote a letter to me, and he wrote a letter to the concerned banks also. I took the letter along with me, and took the students also. Even then, they did not consider it...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You bring it to the notice of the hon. Minister ..*(Interruptions)*...

SHRI C. PERUMAL: They are asking for a collateral security ...*(Interruptions)*... It is true.

SHRI P. CHIDAMBARAM: This is a guideline that has been worked with the IBA. Above a certain limit, collateral is, indeed. It will be completely wrong on my part to tell the banks to lend Rs. 15 lakhs without a collateral.

Up to a certain amount, there is no collateral. Above a certain amount, there is a collateral. Let us see our experience of what is the recovery on these loans, and, then, we can see whether we can relax these guidelines. I am not making a promise that any loan or any amount should be without a collateral. I am sorry, I am not able to make that promise to you. ...*(Interruptions)*...

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: For, students who are studying MBBS, do you know what is the fees there? ...*(Interruptions)*... They have to pay Rs. Two-and-a-half lakhs per year...*(Interruptions)*... For five years, it will be around Rs. 12 lakhs...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: There is no diffculty for MBBS in India. For MBBS in India, the loan is released every year. There is no MBBS course in India where the fee is more than Rs. 7 lakhs a year. Every year the fee is released. If you are asking the money for something else, some other professional...*(Interruptions)*... I cannot help...*(Interruptions)*...

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: They do not sanction money at one go...*(Interruptions)*... Every year they are disbursing it ..*(Interruptions)*... When they sanction the amount, they insist on collateral security. That is the problem...*(Interruptions)*... Poor students will not get the loans.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Send me the example. Give me an example. We will look into it. Within the guidelines there is no collateral.

Hon. Member, Shri Amar Singhji raised issues that have nothing to do with this subject. He was talking about crony capitalism. I thought my reputation is; I have neither friends nor enemies in the corporate sector. I have neither friends nor enemies in the corporate sector. These cases which have been reported in the newspapers relate to assessment years 1998-99, 2000-01 and 2002-03 etc. You know, everybody knows that when a CAG paragraph is there, immediately, Section 147 notice is issued. In all these cases, Section 147 notice has been issued, and assessments are being reopened. There is no friend. There is no enemy. Let me say that I have no friends and no enemies in the corporate sector in these matters.

He mentioned one other case. I am happy to report that we had succeeded in the Tribunal. The matter was pending in the High Court.

He referred to it obliquely. On 2nd May, The Government has succeeded in the High Court also. Therefore, we have defended those cases. We have succeeded in the High Court also. Now, if they go to the Supreme Court, we will have to fight the case in the Supreme Court also. There is no crony capitalism in the UPA Government. Nobody need regard himself as either a friend of the Government or as an enemy of the Government. This Government, in matters relating to finance, would be absolutely scrupulous and will observe financial prudence and scruples. We will not favour anyone. We will not disfavour anyone.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Central Road Fund (Amendment) Bill, 2007.

The Central Road Fund (Amendment) Bill, 2007

THE MINISTER OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI T.R. BAALU): Sir, under section 10 of the Central Road Fund Act, 2000, the Central Government is responsible for allocation of 50 per cent of the cess on high-speed diesel oil for the development and maintenance